Regarding need for immediate release of central share of pending post-matric and other scholarships to SCs/STs in Jharkhand-laid

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी **(**गिरिडीह**) :** पिछले तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) में झारखंड में पोस्ट -मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया गंभीर रूप से बाधित रही है । इसका प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर पड़ा है ? जिन्हें फीस, परीक्षा व शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है और अनेक विद्यार्थी ड्रॉप आउट होने की स्थिति में पहुँच गए हैं । यह शिक्षा के अधिकार तथा सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है । अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से अनुरोध है कि पोस्ट -मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु लंबित केंद्र हिस्सेदारी को तत्काल जारी करें एवं वर्ष-वार एवं श्रेणी-वार लाभार्थियों व भुगतान की स्थिति सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार का संकट न हो इसके लिए एक समयबद्ध स्थायी तंत्र विकसित किया जाए । मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि सरकार इस मुद्दे को अत्यंत प्राथमिकता देकर तात्कालिक हस्तक्षेप करे और छात्रवृत्ति के भुगतान को बिना किसी देरी के सुनिश्चित करे ।

12.08 hrs